इंटरव्यू बूस्टर

आईबीपीएस पीओ स्पेशल

Mahendra's

कंटेंट

आईबीपीएस पीओ साक्षात्कार 2

1. साक्षात्कार प्रक्रिया को समझना 2

2. ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्र 2

3. सामान्यतः पूछे जाने वाले साक्षात्कार प्रश्न 3

4. साक्षात्कार के लिए आवश्यक दस्तावेज 3

5. तैयारी की रणनीति 3

6. साक्षात्कार के लिए पोशाक 4

7. बोनस टिप्स 4

बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2025 में शीर्ष भारतीय बैंक 4

यहां भारत के शीर्ष बैंकों की गहन जानकारी दी गई है, तथा उनकी नींव की जांच की गई है: 4

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ हालिया घटनाक्रम: 7

भारतीय रिजर्व बैंक 8

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हाल के पुरस्कार और मान्यताएँ: 10

हाल ही में उल्लेखनीय निधन 12

हाल ही में नियुक्तियां 14

हाल के पुरस्कार और सम्मान 15

कुछ महत्वपूर्ण विषय 19

वित्तीय समावेशन 22

केंद्रीय बजट 2025-26 22

आईबीपीएस पीओ साक्षात्कार

IBPS PO इंटरव्यू की तैयारी के लिए अपने ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों को प्रदर्शित करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपके इंटरव्यू में उत्कृष्टता प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक व्यापक मार्गदर्शिका दी गई है:

---

1. साक्षात्कार प्रक्रिया को समझना

- पैनल संरचना: आमतौर पर 4-5 सदस्य, जिनमें बैंक अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक शामिल होते हैं।
- अवधि: प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 10-15 मिनट।
- भाषा: यह अंग्रेजी, हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में आयोजित किया जा सकता है।

---

2. ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्र

क. व्यक्तिगत परिचय

- नाम, शैक्षिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक विवरण (संक्षिप्त), शौक और ताकत।
- बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों पर प्रकाश डालें।

बी. बैंकिंग जागरूकता

- बैंकिंग शब्दावली: सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, एनपीए, बेसल मानदंड, आदि।
- हालिया घटनाक्रम: आरबीआई की नीतियां, डिजिटल बैंकिंग रुझान, बैंकों का विलय, नए बैंकिंग उत्पाद आदि।
- समसामयिकी: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं (पिछले 6 माह), विशेषकर अर्थव्यवस्था, वित्त एवं सरकारी योजनाएं।

सी. वित्तीय जागरूकता

- भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें: जीडीपी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, आदि।
- बजट की मुख्य बातें और प्रमुख मौद्रिक नीतियां।
- महत्वपूर्ण वित्तीय संगठन: आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आदि।

डी. सरकारी योजनाएँ

- पीएमजेडीवाई, पीएमएवाई, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, आदि।

ई. आईबीपीएस और बैंकिंग क्षेत्र का ज्ञान

- भर्ती में आईबीपीएस की भूमिका.
- सार्वजनिक बनाम निजी बैंक, उनके अंतर और प्रमुख सुधार।

ऍफ़. आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि

- आपसे स्नातक/स्नातकोत्तर विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा करें।
- आपकी शैक्षिक योग्यता बैंकिंग क्षेत्र में कैसे मदद कर सकती है।

---

3. साक्षात्कार में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यक्तिगत प्रश्न:

- मुझे अपने बारे में बताओ।
- आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
- हम आपको नौकरी क्यों दें?
- आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं?

बैंकिंग से संबंधित प्रश्न:

- बचत खाते और चालू खाते में क्या अंतर है?
- भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें।
- वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं?
- केवाईसी क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है?

समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान:

- हाल ही में आरबीआई की घोषणाओं से संबंधित प्रश्न।
- प्रमुख वैश्विक वित्तीय घटनाएँ.

परिस्थितिजन्य/व्यवहारगत प्रश्न:

- आप किसी कठिन ग्राहक से कैसे निपटेंगे?
- उस समय का वर्णन करें जब आपने किसी टीम का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया हो।

---

4. साक्षात्कार के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आईबीपीएस पीओ साक्षात्कार कॉल लेटर.
- वैध फोटो पहचान प्रमाण (मूल + फोटोकॉपी)।
- जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं कक्षा की मार्कशीट)।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र (मूल + फोटोकॉपी)।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

---

5. तैयारी की रणनीति

- मॉक इंटरव्यू: दोस्तों, मार्गदर्शकों या कोचिंग संस्थानों के साथ अभ्यास करें।
- समसामयिक समाचार पढ़ना: दैनिक समाचारों, विशेषकर बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करें।
- शैक्षणिक पुनरीक्षण: अपने स्नातक विषयों की मूल अवधारणाएँ।

---

6. साक्षात्कार के लिए पोशाक

- पुरुष: औपचारिक शर्ट, पतलून, टाई, औपचारिक जूते।
- महिलाएं: साड़ी, सलवार-कमीज या न्यूनतम सामान के साथ औपचारिक पश्चिमी परिधान।

---

7. बोनस टिप्स

- आँखों का संपर्क बनाए रखें, अच्छा आसन और आत्मविश्वास भरा स्वर बनाए रखें।
- उत्तर देने से पहले ध्यानपूर्वक सुनें।
- यदि आपको उत्तर नहीं पता तो ईमानदार रहें; झांसा देने की कोशिश न करें।

बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2025 में शीर्ष भारतीय बैंक

यहां भारत के शीर्ष 10 बैंकों की सूची दी गई है, जिन्हें उनके बाजार पूंजीकरण (7 जनवरी 2025 तक) के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है।

रैंक और बैंक	प्रकार	मार्केट कैप (लाख करोड़ रुपये)
#1 एचडीएफसी बैंक	निजी	13.11
#2 आईसीआईसीआई बैंक	निजी	9.05
#3 एसबीआई	सार्वजनिक	6.95
#4 कोटक महिंद्रा बैंक	निजी	3.55
#5 एक्सिस बैंक	निजी	3.30
#6 बैंक ऑफ बड़ौदा	सार्वजनिक	1.20
#7 पंजाब नेशनल बैंक	सार्वजनिक	1.19
#8 इंडियन ओवरसीज बैंक	सार्वजनिक	0.97
#9 केनरा बैंक	सार्वजनिक	0.89
#10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	सार्वजनिक	0.87

यहां भारत के शीर्ष बैंकों की गहन जानकारी दी गई है, तथा उनकी नींव का अध्ययन किया गया है:

एचडीएफसी बैंक

- स्थापना तिथि: 30 अगस्त 1994
- एमडी और सीईओ: शशिधर जगदीशन

एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसी मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक के रूप में, यह वित्तीय उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है। अपने मजबूत प्रदर्शन और अभिनव समाधानों के लिए प्रसिद्ध, एचडीएफसी बैंक खुदरा, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी बैंक का विलय उसकी सहयोगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हो गया। यह विलय उपयोगकर्ताओं को बेहतर और अधिक व्यापक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया गया।

एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ के रूप में नामित किया गया है।

आईसीआईसीआई बैंक

- स्थापना तिथि: 5 जनवरी, 1994
- एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी

आईसीआईसीआई बैंक वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह भारत और विदेशों में लाखों ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो अपने ग्राहक-अनुकूल दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धी दरों और उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। अपनी हालिया ईएसजी रिपोर्ट में, आईसीआईसीआई बैंक ने उल्लेखनीय रूप से घोषणा की है कि उसका हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो 2023 में उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण का 21.4 प्रतिशत है, जो लगभग 119 बिलियन डॉलर है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

- स्थापना तिथि: 1 जुलाई, 1955
- अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

मुंबई में मुख्यालय के साथ, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत में इसकी 22,405 शाखाएँ हैं, 23 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, और 36 देशों में 233 से अधिक विदेशी शाखाओं के साथ इसकी विदेशों में मजबूत उपस्थिति है।

वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में एसबीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर भारत की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई।

कोटक महिंद्रा बैंक

- स्थापना तिथि: 21 नवंबर 1985
- एमडी और सीईओ: अशोक वासवानी

कोटक महिन्द्रा बैंक कॉर्पोरेट्स, खुदरा विक्रेताओं और एसएमई सहित विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।

उदय कोटक, जो 21 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ रहे थे, ने पद छोड़ दिया है। उनके उत्तराधिकारी का चयन अभी होना बाकी है, और आरबीआई ने कथित तौर पर उनके उत्तराधिकारी के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की है।

एक्सिस बैंक

- स्थापना तिथि: 3 दिसंबर, 1993
- एमडी और सीईओ: अमिताभ चौधरी

एक्सिस बैंक भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। यह बड़े और मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स, एसएमई और खुदरा व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं में माहिर है। एक्सिस बैंक डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता देता है, एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करता है और विविध खुदरा, कॉर्पोरेट और संस्थागत जरूरतों को पूरा करता है।

एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी दूसरे सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले भारतीय बैंक के सीईओ हैं। बैंक ने इस साल अपने यूजर बेस के लिए एक नेटिव डिजिटल चालू खाता यात्रा लाने के लिए डिजिटल बैंकिंग उद्यम ओपन के साथ भागीदारी की।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी)

- स्थापना तिथि: 20 जुलाई, 1908
- एमडी और सीईओ: देबदत्त चंद

गुजरात के वडोदरा में मुख्यालय वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक के साथ पहली बार तीन-तरफ़ा विलय देखा। एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और विविध बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन शामिल हैं।

हालिया फाइलिंग के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून तिमाही के लिए 4,070.1 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के प्रदर्शन से 88.7 प्रतिशत अधिक है।

पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया (पीएनबी)

- स्थापना तिथि: 19 मई, 1893
- सीईओ: अतुल कुमार गोयल

पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे खुदरा, कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग। वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति से स्पष्ट है। इसका विशाल ग्राहक आधार 180 मिलियन से अधिक है।

स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और प्रारंभिक वर्षों में बैंक के प्रबंधन से निकटता से जुड़े थे।

इंडियन ओवरसीज बैंक

- स्थापित तिथि: 10 फरवरी 1937,
- एमडी और सीईओ: अजय कुमार श्रीवास्तव

1937 में शुरू हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू में विदेशी मुद्रा व्यापार पर केंद्रित था। आज, यह जमा खाते, ऋण और निवेश जैसी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। देशों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के अलावा, इंडियन ओवरसीज बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका में शाखाएँ हैं।

केनरा बैंक

- स्थापना तिथि: 1 जुलाई 1906
- एमडी और सीईओ: के. सत्यनारायण राजू

केनरा बैंक की शुरुआत 1906 में हुई थी। परोपकारी अम्मेबल सुब्बा राव पई ने मैंगलोर में केनरा हिंदू स्थायी निधि की स्थापना की, जो बाद में केनरा बैंक बन गया। 19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह कुल शाखा बैंकिंग के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक भी है। जून 2024 तक, केनरा बैंक सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 9,627 शाखाओं और 12,256 एटीएम/रीसाइक्लर के नेटवर्क के माध्यम

से 11.42 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। सीईओ और एमडी के सत्यनारायण राजू ने हाल ही में घोषणा की कि बैंक वित्त वर्ष 25 में 250 और शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया में है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई)

- स्थापना तिथि: 11 नवंबर, 1919
- सीईओ: ए. मणिमेखलाई

महात्मा गांधी ने 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय का उद्घाटन किया था। देश के विकास के लिए अपने फंड और संसाधनों का उपयोग करने के लिए 14 अन्य बैंकों के साथ 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब UBI की चार शाखाएँ थीं। आज, अप्रैल 2020 में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ विलय के कारण पूरे भारत में इसकी 8700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ हालिया घटनाक्रम:

ऋण वृद्धि में गिरावट

- भारतीय बैंकों ने दिसंबर 2024 में लगातार छठे महीने ऋण वृद्धि में गिरावट का अनुभव किया। एचडीएफसी बैंक विलय प्रभाव को छोड़कर, दिसंबर में साल-दर-साल ऋण वृद्धि 12.4% थी, जबकि पिछले वर्ष यह 15.6% थी। इस मंदी का कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2023 के अंत में लगाए गए सख्त ऋण मानदंड हैं, जो असुरक्षित ऋणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को दिए जाने वाले ऋण में धीमी वृद्धि होती है।

केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा विनिमय

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये ($17.33 बिलियन) की तरलता डालने के लिए $5 बिलियन डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करने वाला है। इस नीलामी से ऋणदाताओं और कॉर्पोरेट ट्रेजरी से मजबूत रुचि आकर्षित होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बीच डॉलर की तरलता को बढ़ाना है।

डिजिटल मुद्रा के साथ फिनटेक एकीकरण

- टाइगर ग्लोबल और पीक XV द्वारा समर्थित फिनटेक फर्म क्रेड भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), ई-रुपी तक पहुँच प्रदान करने वाला पहला फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। शुरुआत में, ई-रुपी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पायलट ने केवल बैंकों को ही पहुँच प्रदान करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, अप्रैल 2024 में, भुगतान फर्मों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। क्रेड ने चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को अपने ई-रुपी वॉलेट तक पहुँच प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसमें यस बैंक ई-रुपी टोकन जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा।

यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन

- उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिससे वह खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक से बदलने की स्थिति में है। RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, इस कदम का उद्देश्य बैंक की पेशकशों और विनियामक स्वतंत्रता को बढ़ाना है, जो इसके लाभदायक स्थिति और विविध पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित है।

रूसी एमआईआर बैंकिंग कार्ड पर विचार

- भारत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए रूस की मीर भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, जिससे भारत आने वाले रूसियों के लिए लेन-देन आसान हो सकता है। चर्चा में राष्ट्रीय मुद्राओं में आपसी व्यापार और वित्तीय संदेश प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के अवसर भारत-रूस सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं।

आरबीआई द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया और जम्मू और कश्मीर बैंक पर विभिन्न विनियामक गैर-अनुपालनों के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। ये कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में विनियामक मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

क्रेडिट कार्ड की वृद्धि में नरमी

- 2024 में नए क्रेडिट कार्ड जोड़ने में मंदी आई, शुद्ध आधार पर 10.1 मिलियन नए क्रेडिट कार्ड जोड़े गए। इस मंदी का कारण बैंकों द्वारा अपनाई गई बढ़ती देनदारियाँ और सावधानीपूर्ण ऋण देने की प्रथाएँ हैं।

व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

- कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो को ₹3,300 करोड़ में खरीद लिया है। इस रणनीतिक कदम से कोटक महिंद्रा बैंक के खुदरा ऋण क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि

- एचडीएफसी बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की सूचना दी है, जिसका मुख्य कारण कृषि ऋण खंड में कमी है। बैंक इन परिसंपत्ति गुणवत्ता चुनौतियों को दूर करने और कम करने के लिए उपाय कर रहा है।

यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन

- उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिसका लक्ष्य यूनिवर्सल बैंक में तब्दील होना है। यह कदम बैंक की विकास रणनीति और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुरूप है।

रूसी एमआईआर बैंकिंग कार्ड की स्वीकृति

- भारत देश में रूसी एमआईआर बैंकिंग कार्ड की स्वीकृति पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। यह पहल द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग बढ़ाने और भारत में रूसी पर्यटकों और व्यापारियों के लिए सुगम लेन-देन की सुविधा प्रदान करने पर व्यापक चर्चा का हिस्सा है।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय रुपये के जारी करने और आपूर्ति को विनियमित करने और देश की बैंकिंग प्रणाली की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 1935 को स्थापित, RBI के प्राथमिक कार्यों में मौद्रिक नीति तैयार करना और उसे लागू करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है।

आरबीआई के संचालन का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो समग्र रणनीतिक दिशा और निगरानी प्रदान करता है। फरवरी 2025 तक, केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

आधिकारिक निदेशक:

- राज्यपाल:
    - श्री संजय मल्होत्रा
        - 11 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे।
        - इससे पहले भारत के राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया।
        - वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
- उप गवर्नर:
    - डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा
    - श्री एम. राजेश्वर राव
    - श्री टी. रवि शंकर
    - श्री स्वामीनाथन जे.

गैर-आधिकारिक निदेशक:

- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत नामित:
    - सुश्री रेवती अय्यर
    - प्रो. सचिन चतुर्वेदी
- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत नामित:
    - श्री सतीश काशीनाथ मराठे
    - श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति
    - श्री आनंद गोपाल महिन्द्रा
    - श्री वेणु श्रीनिवासन
    - श्री पंकज रमनभाई पटेल

केंद्रीय बोर्ड को RBI के मामलों की सामान्य निगरानी और निर्देशन का काम सौंपा गया है। इसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थित स्थानीय बोर्डों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक भारत के चार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्थानीय बोर्ड क्षेत्रीय मामलों पर सलाह देते हैं और केंद्रीय बोर्ड को इनपुट प्रदान करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड की संरचना और कार्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत परिभाषित किया गया है। केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त या नामित किया जाता है, और उनके कार्यकाल, भूमिका और जिम्मेदारियों को अधिनियम में रेखांकित किया गया है।

वर्तमान बोर्ड सदस्यों की व्यापक सूची और आरबीआई के संगठनात्मक ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हाल के पुरस्कार और मान्यताएँ:

आईसीआईसीआई बैंक

- *भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक* : 2024 में यूरोमनी द्वारा इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त, जिसमें 28% वर्ष-दर-वर्ष लाभ वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार शामिल है।
- *भारत में सर्वश्रेष्ठ खुदरा बैंक* : सिंगापुर स्थित प्रकाशन द एशियन बैंकर द्वारा लगातार 11वें वर्ष पुरस्कार दिया गया।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

- *भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2024* : ग्लोबल फाइनेंस मैगज़ीन द्वारा वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार में सम्मानित किया गया।

इंडियन बैंक

- *वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक* और सीईओ : 23वें तमिलनाडु लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में बैंक के प्रदर्शन और एमडी एवं सीईओ एसएल जैन के नेतृत्व को मान्यता देते हुए सम्मानित किया गया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

- *बड़े बैंकों की श्रेणी में विजेता* : 20वें आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया।

इंडसइंड बैंक

- *सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक* : 2024 में भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त।
- *उद्योग को वित्तपोषित करने वाला सर्वश्रेष्ठ बैंक* : मार्च 2024 में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित 50वें भारतीय रत्न और आभूषण पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा।

फेडरल बैंक

- *ईएसजी चैंपियंस ऑफ इंडिया 2024* : डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ईएसजी लीडरशिप समिट 2024 में वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त।
- *सर्वश्रेष्ठ एआई और एमएल बैंक* : आईबीए 19वें वार्षिक प्रौद्योगिकी एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2022-23 में सम्मानित।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

- *वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्यभाषा पुरस्कार* : राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2024 में वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जाएगा।
- *भारत में सर्वश्रेष्ठ मध्यम आकार का बैंक* : मार्च 2024 में गुजरात में बैंकिंग और अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

- *सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक* : लगातार दो वर्षों तक एफई इंडिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित।
- *मास्टर ऑफ रिस्क* : इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स 2023 में मान्यता प्राप्त।

एचडीएफसी बैंक

- *कॉन्शियस कॉरपोरेट ऑफ द ईयर* : 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स से सम्मानित किया जाएगा।

ये सम्मान भारत के बैंकिंग उद्योग में जारी उत्कृष्टता और नवाचार को उजागर करते हैं।

नियामक निकाय

भारत की वित्तीय प्रणाली की देखरेख कई विनियामक निकायों द्वारा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक स्थिरता, पारदर्शिता और विकास सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक विनियामकों में शामिल हैं:

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई):

- भूमिका: केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति को विनियमित करना, मुद्रा जारी करना और बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख करना।
- नव गतिविधि:
    - *तरलता इंजेक्शन:* 31 जनवरी, 2025 को, आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित की, जिससे तरलता बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये डाले गए।
    - *प्रस्तावित तरलता मानदंड:* जुलाई 2024 में, RBI ने बैंकों की तरलता लचीलापन को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इन मानदंडों से सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बैंक अपनी होल्डिंग्स को समायोजित करते हैं।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):

- भूमिका: प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाजार विकास को बढ़ावा देना।
- नव गतिविधि:
    - *विनियामक प्रभाव आकलन:* 31 जनवरी, 2025 की एक सरकारी रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सेबी अपने नियमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं को लागू करे, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई):

- भूमिका: बीमा उद्योग की देखरेख करना, क्षेत्र की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- नव गतिविधि:
    - *विनियामक प्रभाव आकलन:* इसी सरकारी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि IRDAI, अन्य वित्तीय विनियामकों के साथ मिलकर विनियामक परिणामों में सुधार के लिए औपचारिक प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं को अपनाए।

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):

- भूमिका: पेंशन क्षेत्र को विनियमित और विकसित करना, पेंशन निधि की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना।
- नव गतिविधि:
    - *विनियामक प्रभाव आकलन:* 31 जनवरी, 2025 की सरकारी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि पीएफआरडीए अपने विनियमों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं स्थापित करे।

5. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी):

- भूमिका: वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित एक शीर्ष निकाय।
- नव गतिविधि:
    - *नियामक समन्वय:* वित्तीय क्षेत्र की लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए नियामकों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में।

ये विनियामक निकाय भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरबीआई द्वारा प्रस्तावित तरलता मानदंड और औपचारिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए दबाव जैसी हालिया पहल, उभरते वित्तीय परिदृश्यों के अनुकूल होने और विनियामक प्रभावशीलता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

<u>हाल ही में उल्लेखनीय निधन</u>

- नवीन चावला - पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी)
- अतुल परचुरे - वरिष्ठ अभिनेता (57 वर्ष की आयु में निधन)
- कोस्टास सिमिटिस - पूर्व ग्रीक प्रधानमंत्री (88 वर्ष की आयु में निधन)
- एस एम कृष्णा - कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री (92 वर्ष की आयु में निधन)
- डेविड लिंच - महान निर्देशक (78 वर्ष की आयु में निधन)
- मीना गणेश - प्रतिष्ठित मलयालम स्टार
- एच. लक्ष्मणन - टीवीएस में प्रमुख व्यक्ति
- लुइस अयाला - टेनिस लीजेंड (91 वर्ष की आयु में निधन)
- निक्की जियोवानी - अश्वेत कला आइकन (81 वर्ष की आयु में निधन)
- शशि रुइया - अध्यक्ष, एस्सार समूह
- दिल्ली गणेश - वरिष्ठ अभिनेता (80 वर्ष की आयु में निधन)
- एच.एस. सोढ़ी - प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी (86 वर्ष की आयु में निधन)
- श्याम बेनेगल - प्रसिद्ध फिल्म निर्माता (90 वर्ष की आयु में निधन)
- लतिका कट्ट - प्रसिद्ध मूर्तिकार (76 वर्ष की आयु में निधन)
- रतन टाटा - चेयरमैन, टाटा संस (86 वर्ष की आयु में निधन)
- के.एस. मणिलाल - प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री (86 वर्ष की आयु में निधन)
- रॉन एली - टीवी के प्रतिष्ठित 'टार्जन' (86 वर्ष की आयु में निधन)
- डेनिएला चिरिनोस - ओलंपिक साइकिलिस्ट (51 वर्ष की आयु में मृत्यु)
- डेम मैगी स्मिथ - महान अभिनेत्री (89 वर्ष की आयु में निधन)
- उस्ताद ज़ाकिर हुसैन - पद्म भूषण प्राप्तकर्ता (73 वर्ष की आयु में निधन)
- रोहन मीरचंदानी - सह-संस्थापक, एपिगैमिया (42 वर्ष की आयु में निधन)
- डॉ. मनमोहन सिंह - पूर्व प्रधानमंत्री
- शारदा सिन्हा - महान लोक गायिका (72 वर्ष की आयु में निधन)

- पी. जयचंद्रन - प्रसिद्ध पार्श्व गायक
- अमिय कुमार बागची - प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार
- जॉन प्रेस्कॉट - ब्रिटेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री (86 वर्ष की आयु में निधन)
- वसंत अनंत गाडगिल - संस्कृत विद्वान (94 वर्ष की आयु में निधन)
- ओम प्रकाश चौटाला - हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री (89 वर्ष की आयु में निधन)
- तुलसी गौड़ा - 'वनों का विश्वकोश'
- डॉ. के. रामचंद - विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) (82 वर्ष की आयु में निधन)
- नील फ्रेजर - ऑस्ट्रेलियाई डेविस कप आइकन (91 वर्ष की आयु में निधन)
- ओसामु सुजुकी - पूर्व अध्यक्ष, सुजुकी (94 वर्ष की आयु में निधन)
- नरेंद्र चपलगांवकर - न्यायाधीश, लेखक, विद्वान
- पुरूषोत्तम उपाध्याय - प्रसिद्ध गुजराती गायक (90 वर्ष की आयु में निधन)
- डेनिस लॉ - मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के दिग्गज (84 वर्ष की आयु में निधन)
- एमटी वासुदेवन नायर - कालातीत क्लासिक्स के निर्माता
- महेंद्र सिंह मेवाड़ - पूर्व सांसद
- न्यायमूर्ति एच.एस. बेदी - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (78 वर्ष की आयु में निधन)
- पीटर लुंडग्रेन - पूर्व टेनिस खिलाड़ी और रोजर फेडरर के पूर्व कोच
- ब्रेयटेन ब्रेयटेनबाक - प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी लेखक (85 वर्ष की आयु में निधन)
- डॉ. आर. चिदंबरम - भारत के परमाणु दूरदर्शी (88 वर्ष की आयु में निधन)
- राजकुमारी मिकासा - शाही परिवार की सदस्य (101 वर्ष की आयु में मृत्यु)
- पंडित संजय मराठे - प्रसिद्ध गायक और संगीतकार
- जिमी कार्टर - 39वें अमेरिकी राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता (100 वर्ष की आयु में निधन)
- होर्स्ट कोहलर - पूर्व जर्मन राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख (81 वर्ष की आयु में निधन)
- पंडित राम नारायण - क्रांतिकारी सारंगी गुणी (96 वर्ष की आयु में निधन)
- इंद्रानंद सिंह झा - आकाशवाणी दरभंगा रेडियो प्रस्तोता (77 वर्ष की आयु में निधन)
- मोहनराज - वरिष्ठ अभिनेता, प्रतिष्ठित 'कीरिक्कदन जोस' (70 वर्ष की आयु में निधन)
- वरदराओ कमलाकर राव - मृदंगम विद्वान
- ब्रिगेडियर राज मनचंदा - भारतीय स्क्वैश के 'बूढ़े सितारे' (80 वर्ष की आयु में निधन)
- रोहिणी गोडबोले - प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, लैंगिक समानता समर्थक (71 वर्ष की आयु में निधन)
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी - निजता के अधिकार मामले में प्रमुख व्यक्ति (98 वर्ष की आयु में निधन)
- रोहित बल - फैशन आइकन (63 वर्ष की आयु में निधन)
- मदन मोहन सोमतिया - स्वतंत्रता सेनानी, मेवाड़ प्रजा मंडल सदस्य (102 वर्ष की आयु में निधन)
- बिबेक देबरॉय - प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष (69 वर्ष की आयु में निधन)

हाल की नियुक्तियाँ

- अखिल गुप्ता – भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त
- अम्बरीश केंघे – एंजेल वन के ग्रुप सीईओ नियुक्त (मार्च 2025 से प्रभावी)
- श्री आशीष नैथानी – उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त
- अरुणीश चावला – वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव नियुक्त
- ऑस्ट्रेलिया - आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला गुलामी-विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया
- आयुष्मान खुराना – फिक्की फ्रेम्स के 25वें वर्षगांठ संस्करण के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त
- बहादुर सिंह सागू - भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के निर्वाचित अध्यक्ष
- अजय सिंह (बीएफआई प्रमुख) – एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ बोर्ड में शामिल हुए
- भावेश जैन - ट्रांसयूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ नियुक्त
- भुवनेश कुमार – यूआईडीएआई के सीईओ नियुक्त
- डॉ. जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी – ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त
- डॉ. संदीप शाह – एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त
- एमएस धोनी – यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त
- फैज़ अहमद किदवई – डीजीसीए के महानिदेशक नियुक्त
- जी. बालसुब्रमण्यम – मालदीव में उच्चायुक्त नियुक्त
- प्रीति लोबाना – गूगल में भारत प्रमुख नियुक्त
- के संजय मूर्ति - अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त
- ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह – सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त
- हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का राजदूत नामित किया गया
- दिनेश भाटिया – ब्राज़ील में भारतीय राजदूत नियुक्त
- जितेन्द्र पाल सिंह – इजरायल में भारतीय राजदूत नियुक्त
- न्यायमूर्ति आलोक अराधे – बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
- न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा - बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त
- न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
- न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
- न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन – भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हुए
- न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम – एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त
- मनीष सिंघल – एसोचैम के महासचिव नियुक्त
- हिसाशी ताकेउची – मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त
- मिताली राज - एसीए महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त
- नीरज पारख – रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त
- पंकज त्रिपाठी - अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त

- पांच राज्यों के लिए नए राज्यपाल – भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- अमनदीप जोहल – प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ नियुक्त
- राजेश निरवान – नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक नियुक्त
- डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा – भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में पुनः नियुक्त
- सलमान खान - खो-खो विश्व कप के लिए ब्रांड एंबेसडर नामित
- संजीव रंजन – हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव नियुक्त
- महेश कुमार अग्रवाल (आईपीएस) – बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त
- शैलेश कुमार डेवी – ज़ोहो कॉर्प के सीईओ नियुक्त
- अमृत मोहन (एसएसबी प्रमुख) – बीसीएएस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला
- टी. पांडे – राजस्व सचिव नियुक्त
- अरुणीश चावला को दीपम का सचिव नियुक्त किया गया
- वी. नारायणन – इसरो प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार संभाला
- वाल्डेसी उर्कीज़ा - इंटरपोल के नए महासचिव चुने गए
- देशनी नायडू – वेदांता रिसोर्सेज की पहली सीईओ नियुक्त
- विनीत जोशी – उच्च शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला

हाल के पुरस्कार और सम्मान

- आईआईएसआर - सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित।
- एनटीपीसी - एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 में मान्यता प्राप्त।
- सीडब्ल्यूसी - जीईईएफ ग्लोबल वॉटरटेक अवार्ड 2024 से सम्मानित।
- बेयोंसे - "काउबॉय कार्टर" के लिए 2025 ग्रैमी में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।
- केंड्रिक लैमर - "नॉट लाइक अस" के लिए 2025 ग्रैमी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत और रिकॉर्ड दोनों का पुरस्कार हासिल किया।
- चैपल रोआन - 2025 ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार नामित।
- ध्रुवी पटेल - मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2024 का ताज पहनाया गया।
- सूर्यबाला - को उनके उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला।
- शिवांगी देसाई - मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया।
- निकिता पोरवाल - फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया।
- अनिल प्रधान - रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित।
- ऐश्वर्या राय - SIIMA 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
- शाजी एन. करुण - जे.सी. डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित।
- जीआरएसई - सतत शासन चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया।
- पायल कपाड़िया - एक ऐतिहासिक गोल्डन ग्लोब नामांकन अर्जित किया।
- श्री कुरुम्बा ट्रस्ट - ने ग्लोबल सीएसआर ईएसजी अवार्ड 2024 जीता।

- एंग ली - डीजीए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए।
- प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एचएसएल - तीसरे पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार 2024 में विजयी।
- उर्वशी सिन्हा - गेट्स-कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीता।
- अभिनव बिंद्रा - आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित।
- संजना ठाकुर - 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता।
- पद्म पुरस्कार 2025 – घोषित; विजेताओं की पूरी सूची देखें।
- भुवनेश्वर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली - यूएमआई 2024 में चमकी।
- नोबेल पुरस्कार 2024 – विजेताओं की घोषणा; विवरण के लिए सूची देखें।
- शक्तिकांत दास - सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ अर्जित किया।
- वीरता पुरस्कार 2025 – गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाएगा।
- राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया।
- सेल - दूसरे वर्ष भी ग्रेट प्लेस टू वर्क की मान्यता प्राप्त की।
- आरआईएनएल - एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण जीता।
- तानसेन समारोह 2024 - स्वपन चौधरी एवं सानंद न्यास का सम्मान।
- प्रो कबड्डी लीग - सीआईआई अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ खेल लीग' का पुरस्कार जीता।
- सेल - एसएचआरएम एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार में शीर्ष मान्यता प्राप्त हुई।
- जेनी एर्पेनबेक - 'कैरोस' के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता।
- रस्किन बॉन्ड - प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित।
- 2025 राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार – सार्वजनिक सेवा प्रभाव को सम्मानित किया जाएगा।
- विनोद बच्चन - ब्रिटेन की संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित।
- मैग्नस कार्लसन और जुडिट पोल्गर को FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- आरजीआईए - ने लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता।
- सी-डॉट - आपदा लचीलापन प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार जीता।
- पवन सिंधी - ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित।
- कैटलिन सैंड्रा नील - मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया।
- रिया सिंघा - मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता।
- शाहरुख खान - लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया।
- अरुंधति रॉय - प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित।
- सिद्धलिंग पत्तनशेट्टी - गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता।
- हरिमन शर्मा - 'भारत के एप्पल मैन' को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
- सई परांजपे - पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए।
- भारत - एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जीता।

- विक्टोरिया केजर थेलविग - डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनीं।
- बिभब तालुकदार - आईयूसीएन का शीर्ष संरक्षण नेतृत्व पुरस्कार जीता।
- राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, विज्ञान में उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा।
- डॉ. उषा ठाकुर - 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त हुआ।
- न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में *मिसेज* के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता ।
- चंद्रकांत सतीजा - ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित।
- उड़िया कवि प्रतिभा सत्पथी - गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए।
- भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी) - 2024 ओपीसीडब्ल्यू-द हेग पुरस्कार से सम्मानित।
- नेल्सन मंडेला विरासत स्थल - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित।
- *त्रिवेणी* के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता ।
- फ्रांसिस फोर्ड कोपोला - 50वां एएफआई लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
- राजकुमार हिरानी - राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया।
- डब्ल्यूबीएफजेए अवार्ड्स 2024 - अपर्णा सेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- श्री श्री रविशंकर - फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित।
- 26वें सिएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 – क्रिकेट में उत्कृष्टता का जश्न।
- आंध्र प्रदेश - प्राकृतिक खेती मॉडल के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता।
- बीसीसीआई ने टी-20 विश्व चैंपियन भारत के लिए 125 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की।
- WEF 2025 क्रिस्टल अवार्ड्स - डेविड बेकहम, डायने वॉन फ़र्स्टनबर्ग और योहजी यामामोटो को सम्मानित किया गया।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 – घोषित; विजेताओं की पूरी सूची देखें।
- अभिनेता दारासिंग खुराना - ने ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता।
- मारिया विक्टोरिया जुआन - एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता।
- एम्ब्रोस और रुवकुन - जीन विनियमन अनुसंधान के लिए चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- भारतीय शांति सैनिक - संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित।
- *ऑल वी इमेजिन एज लाइट* के लिए कान्स में ग्रैंड प्रिक्स जीता ।
- यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 – गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया जाएगा।
- लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द *फैबल* के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता ।
- मिदोरी पुरस्कार 2024 – कजाकिस्तान और पेरू के मान्यता प्राप्त संरक्षण नेता।
- फिक्की पुरस्कार - आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को भारत के युवा प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया।
- जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफ्री ई. हिंटन - को भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- सुन्दर पिचाई - आईआईटी-खड़गपुर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उत्कृष्ट सेवा के लिए रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा।

- कृष्ण प्रकाश (आईपीएस) – हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित।
- निम्हान्स - स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त किया।
- मेंडिस और ब्यूमोंट - आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स जीते (सितंबर 2024)।
- हयाओ मियाज़ाकी - एनीमेशन में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया।
- राम चरण - मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा।
- डॉ. सौम्या स्वामीनाथन - मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित।
- भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाएं – यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2024 में मान्यता प्राप्त।
- 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 – पूर्ण विजेताओं की घोषणा।
- राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों - पेरिस 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित।
- नागालैंड - कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला।
- विनोद गणात्रा - नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया।
- ट्रैविस हेड - 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में एलन बॉर्डर पदक जीता।
- एम्ब्रोस और रुवकुन - जीन विनियमन अनुसंधान के लिए चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- वैज्ञानिक श्रीनिवास आर. कुलकर्णी - खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार से सम्मानित।
- सखारोव पुरस्कार 2024 - मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को प्रदान किया गया।
- भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 - संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देना।
- एचसीएलटेक की रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला।
- भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
- इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ - चंद्रयान-3 के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त किया।

- बेकर, हसबिस, जम्पर - प्रोटीन अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

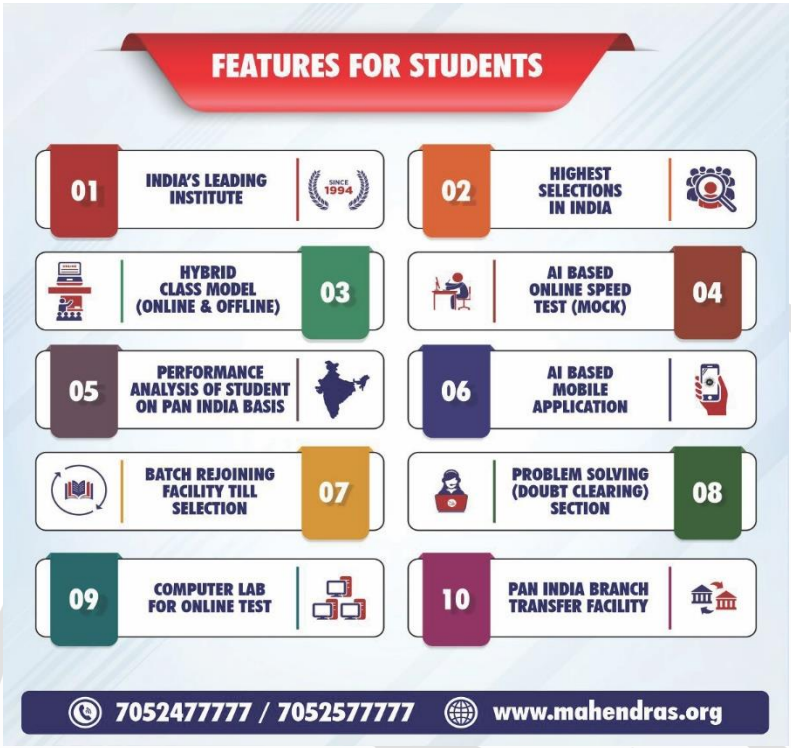

- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 – ग्रामीण शासन और सतत विकास का उत्सव।
- ग्रैमी पुरस्कार 2025 – विजेताओं की पूरी सूची घोषित।
- वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु - को वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला।
- उत्तर प्रदेश की आरती - किंग चार्ल्स तृतीय से अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त किया।
- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 - शांति प्रयासों के लिए डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद को प्रदान किया जाएगा।
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी कमोडोर हेमंत खत्री - पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित।

<u>कुछ महत्वपूर्ण विषय</u>

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मतलब है मशीनों में मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण, जो इंसानों की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम की गई हैं। यह अवधारणा 20वीं सदी के मध्य से चली आ रही है, जिसमें हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। AI में मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विज़न सहित विभिन्न उप-क्षेत्र शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, AI धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा चैटबॉट और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण के माध्यम से परिचालन में क्रांति ला रहा है। उदाहरण के लिए, HDFC बैंक का "ईवा" एक AI-आधारित चैटबॉट है जो ग्राहकों के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक संभालता है। AI बैंकों को परिचालन लागत कम करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद करता है। AI से जुड़े नैतिक विचारों में डेटा गोपनीयता, नौकरी विस्थापन और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह शामिल हैं। AI के अनुप्रयोगों और निहितार्थों को समझना बैंकिंग पेशेवरों के लिए इसके लाभों का जिम्मेदारी से लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।

चैटGPT

- ओपनएआई द्वारा विकसित चैटजीपीटी एक उन्नत भाषा मॉडल है जो उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर मानव जैसा टेक्स्ट उत्पन्न करता है। ओपनएआई, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक एआई शोध संगठन

है, जिसकी स्थापना 2015 में एलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। चैटजीपीटी का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया गया है, जिसमें ईमेल का मसौदा तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना और ग्राहक सेवा प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करना शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र में, चैटजीपीटी जैसी तकनीकें ग्राहक संपर्क को बढ़ा सकती हैं, संचार को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और वित्तीय सलाहकार भूमिकाओं का समर्थन कर सकती हैं। इसका मुख्य लाभ त्वरित, सटीक जानकारी प्रदान करने की इसकी क्षमता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होता है। हालाँकि, चर्चाओं के दौरान डेटा सुरक्षा, विश्वसनीयता और नैतिक उपयोग से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

डीपसीक

- डीपसीक, जिसे आधिकारिक तौर पर हांग्जो डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, हांग्जो, झेजियांग में स्थित एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। जुलाई 2023 में लियांग वेनफ़ेंग द्वारा स्थापित, जो सीईओ के रूप में भी कार्य करते हैं, कंपनी का स्वामित्व और वित्तपोषण चीनी हेज फंड हाई-फ़्लायर द्वारा किया जाता है। डीपसीक ओपन-सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) विकसित करने में माहिर है और इसने ऐसे एआई मॉडल बनाने के लिए ध्यान आकर्षित किया है जो पश्चिमी समकक्षों की तुलना में बहुत कम लागत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए, उनका डीपसीक-आर1 मॉडल ओपनएआई के जीपीटी-4 के बराबर प्रदर्शन करता है

क्रुत्रिम

- क्रुट्रिम एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसकी स्थापना ओला के सह-संस्थापक भाविश अग्रवाल ने की है। 2024 में स्थापित, क्रुट्रिम का उद्देश्य सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय लोकाचार के साथ AI मॉडल विकसित करना है। कंपनी ने अपने मॉडलों को 2 ट्रिलियन से अधिक टोकन पर प्रशिक्षित किया है, जिसमें इंडिक भाषा डेटा का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। फरवरी 2025 में, भाविश अग्रवाल ने क्रुट्रिम में $230 मिलियन के निवेश की घोषणा की, जिससे इसकी क्षमताओं को और बल मिला। क्रुट्रिम ने भारत की पहली फ्रंटियर रिसर्च AI लैब भी लॉन्च की है, जिसमें AI नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अगले साल तक $1.2 बिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता है। बैंकिंग क्षेत्र में, क्रुट्रिम के AI मॉडल क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएँ प्रदान करके ग्राहक जुड़ाव में सुधार कर सकते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। यह मॉडल विदेशी AI तकनीकों पर निर्भरता को कम करते हुए तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर भारत के कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

इजरायल का फिलिस्तीनी समूहों के साथ संघर्ष

- इजराइल और फिलिस्तीनी समूहों, मुख्य रूप से हमास के बीच संघर्ष दशकों से चल रहा है, समय-समय पर बढ़ता रहता है। हाल के संघर्ष क्षेत्रीय विवादों, राजनीतिक तनावों और ऐतिहासिक शिकायतों में निहित हैं। इजराइल के सैन्य अभियानों का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना है, जबकि फिलिस्तीनी स्वायत्तता और राज्य का दर्जा चाहते हैं। यह स्थिति वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित करती

है, जिसमें राष्ट्र अलग-अलग रुख अपनाते हैं। बैंकिंग पेशेवरों के लिए, वैश्विक बाजारों, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव सहित ऐसे संघर्षों के आर्थिक निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है।

यूक्रेन-रूस संघर्ष

- 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंध लगे, जिससे ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य श्रृंखला और वित्तीय बाजार बाधित हुए। इस संघर्ष ने वैश्विक मुद्रास्फीति, तेल की कीमतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव को प्रभावित किया है। बैंकों को इन गतिशीलता को समझना चाहिए क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, विदेशी मुद्रा बाजारों और वैश्विक निवेशों को प्रभावित करते हैं। युद्ध बैंकिंग परिचालन में भू-राजनीतिक जोखिम मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित करता है।

बांग्लादेश की स्थिति

- बांग्लादेश ने हाल ही में राजनीतिक अशांति, मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा की कमी सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। पिछले दशक में तेजी से विकास के बावजूद, देश शासन संबंधी मुद्दों, श्रम अशांति और जलवायु संबंधी कमजोरियों से जूझ रहा है। बांग्लादेश में परिचालन करने वाले या उसके साथ काम करने वाले भारतीय बैंकों के लिए, जोखिम मूल्यांकन और सीमा पार व्यापार वित्त के लिए इन कारकों को समझना आवश्यक है। यह स्थिति विदेशी निवेश को आकर्षित करने और मजबूत वित्तीय प्रणालियों को बनाए रखने के लिए आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता को उजागर करती है।

मणिपुर ड्रग युद्ध

- भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, तस्करी और नशे की लत सहित नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से जूझ रहा है। "गोल्डन ट्राएंगल" (दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख नशीली दवा उत्पादक क्षेत्र) से इस क्षेत्र की निकटता समस्या को और बढ़ा देती है। सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए पहल शुरू की है, जिसमें कानून प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। बैंक सख्त केवाईसी मानदंड सुनिश्चित करके और नशीली दवाओं की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लेनदेन की निगरानी करके भूमिका निभाते हैं।

महाकुंभ मेला

- कुंभ मेला एक प्रमुख हिंदू तीर्थयात्रा और त्यौहार है जो भारत के चार पवित्र स्थानों: प्रयागराज (इलाहाबाद), हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में एक चक्र में मनाया जाता है। त्यौहार को इसकी आवृत्ति और महत्व के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
    i. **कुंभ मेला** : विशिष्ट ग्रह स्थिति के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में चारों स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
    ii. **अर्ध कुंभ मेला** : हर 6 साल में, विशेष रूप से हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है।

iii. **पूर्ण कुंभ मेला** : चार स्थलों पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए एक अन्य शब्द।

iv. **महाकुंभ मेला** : प्रत्येक 144 वर्ष बाद (12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद) प्रयागराज में विशेष रूप से आयोजित होता है।

- सबसे हालिया महाकुंभ मेला 14 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया गया था, जिसमें लाखों श्रद्धालु आए थे, जिन्होंने गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर अनुष्ठानिक स्नान में भाग लिया था। यह आयोजन अपनी विशाल सभाओं, आध्यात्मिक महत्व और नागा साधुओं जैसे तपस्वी समूहों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सूचकांक

- भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापता है। सूचकांक 0 से 100 तक होता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण समावेशन को दर्शाता है। मार्च 2024 तक, FI-सूचकांक 64.2 पर था, जो मार्च 2023 में 60.1 से ऊपर था, जो सभी प्रमुख मापदंडों में वृद्धि को दर्शाता है।

खाता स्वामित्व

- ग्लोबल फ़ाइंडेक्स डेटाबेस के अनुसार, भारत में औपचारिक बैंक खाता रखने वाले वयस्कों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। 2011 में, केवल 35% वयस्कों के पास औपचारिक खाता था, जो 2014 तक बढ़कर 53% और 2017 में 81% हो गया। हालाँकि, 2021 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 78% हो गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- अगस्त 2014 में शुरू किया गया, PMJDY एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। अगस्त 2023 तक, इस योजना के तहत 500 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि ₹2 ट्रिलियन से अधिक है। प्रति खाता औसत जमा राशि में भी लगातार वृद्धि देखी गई है, जो अगस्त 2023 में ₹4,063 तक पहुँच गई है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई)

- 2022-23 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग 211 MFI हैं, जिनकी संयुक्त परिसंपत्ति का आकार ₹3,48,339 करोड़ है। ये संस्थाएँ आबादी के वंचित और बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डिजिटल वित्तीय सेवाएँ

- डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाना भारत में वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) जैसी पहलों ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने छोटे निवेशकों के बीच व्यवस्थित बचत को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे आकार की निवेश योजनाएँ शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है।

- इन प्रगतियों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खास तौर पर दूरदराज के इलाकों तक पहुँचने और वित्तीय सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करने में। पूरे देश में व्यापक वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास ज़रूरी हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें

भाग ए

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

बजट अनुमान 2025-26

- उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः ₹ 34.96 लाख करोड़ और ₹ 50.65 लाख करोड़ अनुमानित हैं।
- शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधार 14.82 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में ₹11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है।

कृषि विकास का पहला इंजन

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण

- कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दालों में आत्मनिर्भरता

- सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करेगी।
- नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों की खरीद करेंगे।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

- राज्यों के साथ साझेदारी में किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड

- मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन

- उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उच्च उपज वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार तथा 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मत्स्य पालन

- सरकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी, जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कपास उत्पादकता मिशन

- कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5-वर्षीय मिशन की घोषणा की गई।

केसीसी के माध्यम से उन्नत ऋण

- केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा ₹ 3 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख की जाएगी।

असम में यूरिया संयंत्र

- असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

एमएसएमई विकास का दूसरा इंजन

एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन

- सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स

- विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के नए अंशदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।

पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना

- अगले पांच वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यम लगाने वालों को 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई।

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना

- भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक फोकस उत्पाद योजना की घोषणा की गई है, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होगा।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

- एक योजना उच्च गुणवत्ता वाले, अनूठे, नवोन्मेषी और टिकाऊ खिलौने बनाने के लिए भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा की गई।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए समर्थन

- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी।

विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

- "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई।

विकास का तीसरा इंजन है निवेश

I. **लोगों में निवेश**

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

अटल टिंकरिंग लैब्स

- अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

- स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई।

कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- हमारे युवाओं को "भारत के लिए निर्माण, विश्व के लिए निर्माण" के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

- 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र

- शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से की जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

- अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे अगले 5 वर्षों में सीटों की संख्या 75000 हो जाएगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर

- सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करेगी, 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका को मजबूत बनाना

- शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना की घोषणा की गई, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके और उन्हें स्थायी आजीविका प्राप्त करने में मदद मिल सके।

पीएम स्वनिधि

- बैंकों से ऋण में वृद्धि, 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड तथा क्षमता निर्माण सहायता के साथ योजना का पुनर्गठन किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

- सरकार गिग-वर्कर्स के लिए पहचान पत्र, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करेगी।

II. अर्थव्यवस्था में निवेश

बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी

- बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों को पीपीपी मोड में परियोजनाओं की 3 साल की पाइपलाइन के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया गया, राज्यों को भी प्रोत्साहित किया गया।

बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को सहायता

- पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30

- 2025-30 के लिए दूसरी योजना में नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की घोषणा की गई।

जल जीवन मिशन

- मिशन को कुल व्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ाया जाएगा।

शहरी चुनौती निधि

- 'शहरों को विकास केन्द्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई, 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित।

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाएगा।
- 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी, 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे।

जहाज निर्माण

- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति में सुधार किया जाएगा।
- निर्दिष्ट आकार से बड़े बड़े जहाजों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

समुद्री विकास निधि

- 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा, जिसमें 49 प्रतिशत तक का योगदान सरकार द्वारा तथा शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र द्वारा दी जाएगी।

उड़ान - क्षेत्रीय संपर्क योजना

- अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने तथा 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गई।
- इसके अलावा पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा।

बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

- बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई, इसके अलावा पटना हवाई अड्डे की क्षमता में विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की भी घोषणा की गई।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

- बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।

खनन क्षेत्र में सुधार

- महत्वपूर्ण खनिजों की निकासी के लिए नीति बनाई जाएगी।

स्वामी फंड 2

- सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से, एक लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई।

रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन

- देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।

III. नवप्रवर्तन में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

- ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करना।

डीप टेक फंड ऑफ फंड्स

- अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी।

पीएम रिसर्च फेलोशिप

- आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ।

फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

- दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन

- आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की गई।

ज्ञान भारतम मिशन

- हमारी पाण्डुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर ज्ञान भारतम मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक पाण्डुलिपियों को शामिल किया जाएगा।

विकास के चौथे इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्धन मिशन

- वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी।

भारतट्रेडनेट

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'भारत ट्रेडनेट' (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान हेतु एक एकीकृत मंच होगा।

जी.सी.सी. के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

- उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शन के रूप में एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।

ईंधन के रूप में सुधार: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा उन कम्पनियों के लिए 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी जो अपना सम्पूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं।

NaBFID द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा

- एनएबीएफआईडी बुनियादी ढांचे के लिए कॉर्पोरेट बांड के लिए 'आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा' स्थापित करेगा।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढांचा विकसित करेंगे।

पेंशन क्षेत्र

- पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा।

विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति

- सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों, प्रमाणनों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक

- प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक शुरू किया जाएगा।

जन विश्वास विधेयक 2.0

- जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।

भाग बी

प्रत्यक्ष कर

- नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय (अर्थात् पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक कोई व्यक्तिगत आयकर देय नहीं होगा।
- 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।
- नये ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथों में अधिक धन बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- नया आयकर विधेयक स्पष्ट और सीधा होगा ताकि करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना सरल हो सके, जिससे कर निश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।
- प्रत्यक्ष करों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व छूट जाएगा।

- **संशोधित कर दर संरचना**
  - नई कर व्यवस्था में संशोधित कर दर संरचना निम्नानुसार होगी:

0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	इसे स्वीकार करो
20- 24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- **कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना**
  - स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाना, दरों की संख्या और सीमा को कम करना, जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये हो गई।
- किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।
- आरबीआई की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण पर स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई।
- उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों में लागू होंगे।
- विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीसीएस के भुगतान में देरी के मामलों को अपराध से मुक्त किया जाएगा।

- **अनुपालन बोझ को कम करना**
- छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके उनके अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा।
- स्व-अधिभोग वाली संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य मानने का लाभ, बिना किसी शर्त के, दो ऐसी स्व-अधिभोग वाली संपत्तियों के लिए बढ़ाया जाएगा।

- **व्यापार करने में आसानी**
- तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने हेतु एक योजना की शुरूआत।
- मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के दायरे का विस्तार।
- 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से की गई निकासी पर छूट।
- एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी सामान्य एनपीएस खातों के समान ही सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो समग्र सीमाओं के अधीन हैं।
- **रोजगार और निवेश**

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं के लिए कर निश्चितता

- उन गैर-निवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था जो किसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है।
- निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों का भंडारण करने वाले गैर-निवासियों के लिए कर निश्चितता हेतु एक सुरक्षित बंदरगाह की शुरूआत।

अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार कर योजना

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों को मौजूदा टन भार कर योजना का लाभ दिया जाएगा।

स्टार्ट-अप्स के निगमन के लिए विस्तार

1.4.2030 से पहले निगमित स्टार्ट-अप्स को लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगमन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

श्रेणी I और श्रेणी II के एआईएफ को प्रतिभूतियों से प्राप्त लाभ पर कराधान की निश्चितता, जो बुनियादी ढांचे और अन्य ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं

- **सॉवरेन और पेंशन फंड के लिए निवेश की तिथि का विस्तार**

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स में निवेश करने की तिथि को पांच वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 कर दिया गया है।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

i. सात टैरिफ दरें हटाई जाएँगी। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद, 'शून्य' दर सहित केवल आठ टैरिफ दरें ही शेष रहेंगी।

ii. कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जहां शुल्क का प्रभाव मामूली रूप से कम हो जाएगा, प्रभावी शुल्क प्रभाव को व्यापक रूप से बनाए रखने के लिए उचित उपकर लागू करें।

iii. एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसलिए 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी गई है, जो उपकर के अधीन हैं।

अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ रुपये का राजस्व माफ किया जाएगा ।

औषधियों/औषधियों के आयात पर राहत

- 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट दी गई।
- 6 जीवनरक्षक दवाओं पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लगेगा।
- दवा कम्पनियों द्वारा संचालित रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्दिष्ट औषधियों और औषधियों को बी.सी.डी. से पूर्ण छूट दी गई; 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और औषधियों को जोड़ा गया।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को समर्थन

- **महत्वपूर्ण खनिज** :
    - कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है।
- **वस्त्र:**
    - दो अन्य प्रकार के शटल-रहित करघों को कपड़ा मशीनरी से पूर्ण छूट दी गई।
    - बुने हुए कपड़ों पर बीसीडी दर को "10% या 20%" से संशोधित कर "20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" कर दिया गया है।

- **इलेक्ट्रॉनिक सामान** :
    - इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी 10% से बढ़कर 20% हो गई।
    - ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी घटाकर 5% कर दिया गया।
    - ओपन सेल के भागों पर बी.सी.डी. से छूट दी गई।
- **लिथियम आयन बैटरी** :
    - ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं तथा मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई।
- **शिपिंग क्षेत्र** :
    - जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या भागों पर बीसीडी की छूट को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
    - जहाज तोड़ने के लिए भी यही व्यवस्था जारी रहेगी।
- **दूरसंचार** :
    - कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विचों पर बीसीडी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया।

निर्यात संवर्धन

- **हस्तशिल्प सामान** :
    - निर्यात की समयावधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई, आवश्यकता पड़ने पर इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।
    - नौ वस्तुओं को शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में जोड़ा गया।
- **चमड़ा क्षेत्र:**
    - गीले नीले चमड़े पर बीसीडी पूरी तरह से छूट दी गई।
    - क्रस्ट चमड़े को 20% निर्यात शुल्क से छूट दी गई।
- **समुद्री उत्पाद** :
    - फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) के विनिर्माण और इसके एनालॉग उत्पादों के निर्यात के लिए बीसीडी को 30% से घटाकर 5% कर दिया गया।
    - मछली और झींगा आहार के विनिर्माण के लिए मछली हाइड्रोलाइज़ेट पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- **रेलवे माल के लिए घरेलू एमआरओ** :
    - रेलवे एमआरओ को मरम्मत सामग्री के आयात के मामले में विमान और जहाज एमआरओ के समान लाभ मिलेगा।
    - ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है तथा इसे आगे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ट्रेड फ़ैसिलिटेशन

- **अनंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा** :

- अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- **स्वैच्छिक अनुपालन:**
  - आयातकों या निर्यातकों को माल की निकासी के बाद, स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एक नया प्रावधान शुरू किया गया है।
- **अंतिम उपयोग के लिए विस्तारित समय** :
  - प्रासंगिक नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।
  - ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय केवल त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होगा।